संख्या-17/2019/688/38-6-19-03(एसआरएलएम)/2019

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-20 नवम्बर, 2019

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत नेशनल रूरल इकनामिक ट्रान्सफारमेसन प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2579/एनआरएलएम /लेखा-1630/2019-20, दि0-09.10.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12014/01/2017-आरएल(एनआरईटीपी-12), दि0-13.09.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में केन्द्रांश(60 प्रतिशत) प्रथम किश्त रू0-2286.00 लाख(रूपये बाइस करोड छियासी लाख मात्र) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त केन्द्रांश(60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(40 प्रतिशत) की धनराशि रू0-1524.00 लाख बनती है। इस प्रकार अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-2286.00 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-1524.00 लाख सहित कुल धनराशि रू0-3810.00 लाख(रूपये अडतीस करोड दस लाख मात्र) अवमुक्त किया जाना है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत रू0-64581.76 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्र्तगत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से भारत सरकार के पत्र दि0-13.09.2019 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त की धनराशि रू0-2286.00 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-1524.00 लाख कुल धनराशि रू0:3810.00 लाख (रूपये अडतीस करोड दस लाख मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृती किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किय जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दि0-13.09.2019 की शर्तों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दि0-22 मार्च, 2019 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-870/दस-19, दि0-08.11.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहें है।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

संख्या-17/2019/688(1)/38-6-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।